बीबीआईएन कार्यशाला में क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा

नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव ने कहा, सड़कों के साथ-साथ जलमार्गों में बेहतर कनेक्टिविटी निर्बाध संपर्क के लिए जरूरी

लखनऊ। भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) उपक्षेत्र में सीमा पर अवस्थापना सुविधाएं और बेहतर कनेक्टिविटी पर उच्चस्तरीय कार्यशाला में नेपाल के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसका एक पहलू नेपाल के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना भी था। नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत को बड़े भाई की भूमिका से बचते हुए अपने पड़ोसियों का समर्थन करना चाहिए। सड़कों के साथ-साथ जलमार्गों में बेहतर कनेक्टिविटी निर्बाध संपर्क के लिए अत्यंत आवश्यक है।

गोमतीनगर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यशाला में प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। बीते आठ वर्षों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में 15% की वृद्धि दर भी शामिल है। उन्होंने यूपी-नेपाल सीमा संपर्क को सशक्त करने पर जोर देते हुए कहा कि नेपाल और अन्य बीबीआईएन देशों के साथ मजबूत संपर्क आपसी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस दिशा में नीति आयोग और इन्वेस्ट यूपी के प्रयासों की सराहना की। ठाकुर ने उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच लगभग 600 किमी की साझा सीमा का उल्लेख करते हुए व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में साझा उत्तरदायित्व पर जोर दिया।

चर्चा का मुख्य फोकस उपलब्धता, गुणवत्ता और स्थिरता रहा, जिसमें क्षेत्रीय विकास के लिए एकतरफा, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय हस्तक्षेपों पर विचार किया गया। वरिष्ठ फेलो डॉ. कॉन्स्टेंटिनो जेवियर और सहायक फेलो रिया सिन्हा ने भारत-नेपाल संबंधों में उत्तर प्रदेश की रणनीतिक भूमिका को विस्तार से समझाया। व्यूरो